अध्याय-5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

अध्याय 5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

5.1 परिचय

यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) शब्द में वे सरकारी कंपनियाँ और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित अन्य कंपनियों को भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एसपीएसयू) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों के पास या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की गई हो और इसमें वैसी कंपनी भी शामिल है जो एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी भी अन्य कंपनी को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के रूप में संदर्भित किया जाता है।

31 मार्च 2023 तक राज्य में एसपीएसई की कुल संख्या 32 थी। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2020-21 से 2022-23 के भीतर प्राप्त नवीनतम अंतिम खातों के आधार पर, 16 एसपीएसई (15 सरकारी कंपनियाँ और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी) को इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

5.2 अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जो सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके तहत बनाए गए विनियम के साथ पढ़ा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी कंपनियों के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करता है और खातों का लेखापरीक्षा करने के तरीके पर निर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का भी अधिकार है। कुछ वैधानिक निगमों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार उनके खातों का लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है।

5.3 इस अध्याय में क्या शामिल है

यह अध्याय राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का अवलोकन है जैसा कि उनके खातों से पता चलता है।

5.4 एसपीएसई और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में उनका योगदान

एसपीएसई में राज्य सरकार की कंपनियाँ और वैधानिक निगम शामिल हैं। एसपीएसई की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को चलाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने के लिए की गई है। 31 मार्च 2023 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत झारखण्ड में 32 एसपीएसई (तीन[1] निष्क्रिय सरकारी कंपनियों और एक[2] सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) थे। 16 एसपीएसई, जिनके पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में से किसी एक के खाते प्राप्त हुए हैं, **परिशिष्ट 5.1** में दिए गए हैं। 16 एसपीएसई जिनके खाते तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, उन्हें **परिशिष्ट 5.2** में दिखाया गया है।

झारखण्ड में स्थापना के बाद से तीन निष्क्रिय एसपीएसई हैं, जिनमें पूँजी (₹ 1.10 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 47.89 करोड़) के लिए ₹ 48.99 करोड़ का निवेश है। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि इन निष्क्रिय एसपीएसई में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देता है। पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने को उनके बोर्ड[3] द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

एसपीएसई के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एसपीएसई की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत एसपीएसई और स.रा.घ.उ. का टर्नओवर **तालिका 5.1** में दिया गया है।

---

1 *करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल), झारबिहार कोलियरी लिमिटेड*

2 *झारखण्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड*

3 *पीईएल: 5वीं एजीएम (15 सितंबर 2017), जेसीएल: 16वीं (02 फरवरी 2018)*

तालिका 5.1: झारखण्ड के स.रा.घ.उ. की तुलना में एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
विद्युत क्षेत्र एसपीएसई	5,018.57	6,138.67	6,138.67
गैर-विद्युत क्षेत्र एसपीएसई	63.02	81.25	81.25
कुल	**5,081.59**	**6,219.92**	**6,219.92**
पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन	-9.36	22.40	0.00
झारखण्ड की स.रा.घ.उ.	2,96,664	3,58,863	3,93,722
झारखण्ड के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर का प्रतिशत	1.71	1.73	-

स्रोत: 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर संकलन को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में लिया गया क्योंकि 2022-23 के लिए कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं था और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और योजना और विकास विभाग, भारत सरकार के अनुसार स.रा.घ.उ. आंकड़े।

16 एसपीएसई का टर्नओवर 2020-21 में ₹ 5,081.59 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 6,219.92 करोड़ हो गया। जैसा कि **तालिका 5.1** में दिखाया गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर वृद्धि (-) 9.36 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 के दौरान 22.40 प्रतिशत दर्ज की गई।

झारखण्ड के स.रा.घ.उ. में एसपीएसई का योगदान 2020-21 में 1.71 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 1.73 प्रतिशत हो गया।

5.5 एसपीएसई में निवेश और बजटीय सहायता

एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

30 सरकारी कंपनियों और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि 31 मार्च 2023 के अंत तक **तालिका 5.2** में दी गई है।

तालिका 5.2: सरकारी कंपनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2022 तक			31 मार्च 2023 तक		
	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
राज्य सरकार	9,456.18	16,926.61	26,382.79	9,509.80	19,967.47	29,477.27
अन्य (सरकारी कंपनियों सहित)	52.34	2,163.01	2,215.35	52.34	2,531.97	2,584.31
कुल निवेश	**9,508.52**	**19,089.62**	**28,598.14**	**9,562.14**	**22,499.44**	**32,061.58**
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.45	88.67	92.25	99.45	88.75	91.94

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों को अधिक कंपनियों से वर्ष का लेखा-जोखा प्राप्त होने के बाद सुधार/संशोधित किया गया है।

राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा, सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (झारखण्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) में निवेश की गई पूँजी वर्ष 2022-23 तक ₹ 19.80 करोड़ थी जो **तालिका 5.2** में शामिल है।

2022-23 के दौरान, 31[4] एसपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी होल्डिंग में ₹ 53.62 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में इक्विटी में निवेश 2021-22 में ₹ 9,456.18 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 9,509.80 करोड़ हो गया। विद्युत क्षेत्र के दो एसपीएसई, जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल का योगदान क्रमशः ₹ 3,246.45 करोड़ और ₹ 1,598.96 करोड़ था।

31 मार्च 2023 तक 31 कार्यरत एसपीएसई में क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3: एसपीएसई में क्षेत्रवार निवेश

विवरण	निवेश[5] (₹ करोड़ में)					कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण	
विद्युत क्षेत्र	9,121.25	9,120.15	22,411.14	19,916.20	31,532.39	98.35
गैर-विद्युत क्षेत्र	440.89	389.65	88.30	51.27	529.19	1.65
कुल	**9,562.14**	**9,509.80**	**22,499.44**	**19,967.47**	**32,061.58**	**100.00**

स्रोत: जानकारी एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई

एसपीएसई में निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई पर था, जिन्हें 31 मार्च 2023 तक कुल निवेश ₹ 32,061.58 करोड़ का 98.35 प्रतिशत (₹ 31,532.39 करोड़) प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार की हिस्सेदारी कुल निवेश ₹ 32,061.58 करोड़ का 91.94 प्रतिशत (₹ 29,477.27 करोड़) थी।

5.6 एसपीएसई से प्रतिफल

5.6.1 एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के आधार पर, गैर-विद्युत क्षेत्र से संबंधित सात एसपीएसई ने 2020-21 में ₹ 31.11 करोड़ का लाभ दर्ज किया और 2021-22 में 10 एसपीएसई (दो विद्युत और आठ गैर-विद्युत क्षेत्र) ने वर्ष के दौरान ₹ 53.57 करोड़ का लाभ दर्ज किया जिसमे से 77.26 प्रतिशत का योगदान दो एसपीएसई (जेयूयूएनएल और जेएसबीसीसीएल) द्वारा किया गया था। वित्त वर्ष

[4] *झारखण्ड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से कोई जानकारी/लेखा प्राप्त नहीं हुआ है*

[5] *निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।*

2020-21 और 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई **तालिका 5.4** में दर्शाये गए हैं।

तालिका 5.4: वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	2020-21		2021-22	
		शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
1	ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण	4.94	15.88	1.30	2.43
2	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	1.30	4.18	0.96	1.79
3	झारखण्ड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	0.09	0.29	0.79	1.47
4	झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	9.80	31.50	4.02	7.50
5	झारखण्ड रेलवे आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.06	0.19	-	-
6	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	-	-	0.33	0.62
7	झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.13	6.85	2.13	3.98
8	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	12.79	41.11	29.49	55.05
9	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	2.63	4.91
10	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	11.90	22.21
11	पतरातू एनर्जी लिमिटेड	-	-	0.02	0.04
कुल		**31.11**	**100.00**	**53.57**	**100.00**

वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ कमाने वाले उपरोक्त सात एसपीएसई में से, केवल एक एसपीएसई अर्थात, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (जेएसबीसीसीएल) ने ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया था, जबकि नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त 10 लाभ कमाने वाले एसपीएसई में से, केवल दो एसपीएसई अर्थात जेयूयूएनएल और जेएसबीसीसीएल ने ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया था।

5.6.2 एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले एसपीएसई को राज्य सरकार द्वारा रखी गई इक्विटी पर न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना आवश्यक है।

5.7 ऋण भुगतान

5.7.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कंपनी की ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले की कमाई को उसी अवधि के ब्याज व्यय द्वारा विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की कर्ज पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी पिछले तीन वर्षों में ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। इस संबंध में तीन[6] कार्यात्मक बिजली क्षेत्र एसपीएसई की स्थिति **तालिका 5.5** में दिखाई गई है।

तालिका 5.5: एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	एसपीएसई की संख्या[7]	1 के बराबर या उससे अधिक आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या	1 से कम आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या
2020-21	936.93	0	3	0	3
2021-22	1,049.56	14.15	3	1	2
2022-23	1,049.56	14.15	3	1	2

स्रोत: 30 सितंबर 2023 तक एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वार्षिक खाते। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में लिया गया है क्योंकि 2022-23 के लिए कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं था।

जैसा कि **तालिका 5.5** में दिखाया गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान तीन कार्यात्मक विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई का आईसीआर एक से कम था, जबकि दो कार्यात्मक विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई[8] का आईसीआर वर्ष 2021-22 के दौरान एक से कम था, जो अपने ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त कमाई का संकेत था और दिवालियापन के एक उच्च जोखिम का संकेत था।

5.7.2 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार द्वारा तीन विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल) को प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋण पर 5,943.53 करोड़ रुपये का ब्याज बकाया था। बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 5.6** में दर्शाया गया है।

---

6 *जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल।*

7 *सरकार से जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल द्वारा लिए गए ऋण।*

8 *जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल*

तालिका 5.6: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	ऋण पर बकाया ब्याज	बकाया ऋणों पर ब्याज		
			एक वर्ष से कम	1 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
विद्युत क्षेत्र					
1	जेबीवीएनएल	2,864.76	544.18	970.60	1,349.98
2	जेयूएसएनएल	3,033.21	501.43	1,002.86	1,528.92
3	जेयूयूएनएल	45.56	3.95	13.03	28.58
कुल		**5,943.53**	**1,049.56**	**1,986.49**	**2,907.48**

स्रोत: 30 सितंबर 2023 तक एसपीएसई के अंतिम रूप दिए गए नवीनतम वार्षिक खाते

तालिका 5.6 से देखा जा सकता है कि तीन वर्षों से अधिक समय से ₹ 2,907.48 करोड़ का ब्याज बकाया था। कंपनियाँ ब्याज के साथ-साथ बकाया ऋण का मूलधन भी चुकाने में विफल रही थीं।

5.8 एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन

5.8.1 नियोजित पूँजी पर रिटर्न

नियोजित पूँजी पर रिटर्न (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उसकी पूँजी नियोजित करने की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना किसी कंपनी की ब्याज और करों से पहले की कमाई (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[9] से विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 16 एसपीएसई (6 विद्युत और 10 गैर-विद्युत क्षेत्र) के आरओसीई का विवरण **तालिका 5.7** में दिया गया है।

तालिका 5.7: नियोजित पूँजी पर रिटर्न

वर्ष	वर्षवार/क्षेत्रवार विवरण	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2022-23	विद्युत क्षेत्र	-2,583.55	8,923.22	-28.95
	गैर-विद्युत क्षेत्र	55.26	547.14	10.10
	कुल	**-2,528.29**	**9,470.36**	**-26.70**
2021-22	विद्युत क्षेत्र	-2,583.55	8,923.22	-28.95
	गैर-विद्युत क्षेत्र	55.26	547.14	10.10
	कुल	**-2,528.29**	**9,470.36**	**-26.70**
2020-21	विद्युत क्षेत्र	-2,711.66	11,740.56	-23.10
	गैर-विद्युत क्षेत्र	33.76	493.74	6.84
	कुल	**-2,677.90**	**12,234.30**	**-21.89**
कुल योग		**-7,734.48**	**31,175.02**	**-24.81**

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में दिखाया गया था क्योंकि 2022-23 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

[9] *नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + नि:शुल्क रक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।*

तालिका 5.7 से यह देखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई 2020-21 में (-) 23.10 प्रतिशत था जो 2021-22 और 2022-23 के दौरान घटकर (-) 28.95 प्रतिशत हो गया जो विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई के घाटे में कमी के कारण था (2020-21 के दौरान ₹ 2,711.66 करोड़ से 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान ₹ 2,583.55 करोड़)।

हालाँकि, 2020-21 से 2022-23 अवधि के दौरान गैर-विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई 6.84 प्रतिशत से बढ़कर 10.10 प्रतिशत हो गया।

5.8.2 एसपीएसई द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिससे यह आकलन किया जाता है कि किसी कंपनी की संपत्ति का उपयोग मुनाफा कमाने के लिए कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आरओई की गणना शुद्ध आय (अर्थात, करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के फंड से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्याएं हो|

शेयरधारकों के फंड की गणना भुगतान की गई पूँजी और मुक्त भंडार में से संचित घाटे और स्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है जिससे यह पता चलता है कि यदि सभी संपत्तियाँ बेच दी गईं और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया गया तो कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितना बचा होगा। एक सकारात्मक शेयरधारक के फंड से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियाँ संपत्ति से अधिक हैं।

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एसपीएसई का क्षेत्रवार आरओई **तालिका 5.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8: एसपीएसई की इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

वर्षवार क्षेत्र-वार ब्रेक-अप	ईएआईटी/शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारक निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2022-23			
विद्युत क्षेत्र	-2,585.80	-9,954.76	-
गैर-विद्युत क्षेत्र	41.65	502.97	8.28
कुल	**-2,544.15**	**-9,451.79**	**-**
2021-22			
विद्युत क्षेत्र	-2,585.80	-9,954.76	-
गैर-विद्युत क्षेत्र	41.65	502.97	8.28
कुल	**-2,544.15**	**-9,451.79**	**-**
2020-21			
विद्युत क्षेत्र	-2,711.71	-7,199.86	-
गैर-विद्युत क्षेत्र	21.01	448.98	4.68
कुल	**-2,690.70**	**-6,150.88**	**-**

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में दिखाया गया था क्योंकि 2022-23 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

तालिका 5.8 से देखा जा सकता है कि गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओई 2020-21 में 4.68 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 8.28 प्रतिशत हो गया। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए विद्युत् क्षेत्र का आरओई निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि शुद्ध आय और शेयरधारक की इक्विटी दोनों नकारात्मक थी।

5.8.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न की दर

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, एसपीएसई में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार धन को वर्ष-वार सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए धन की न्यूनतम लागत माना जाता है, पर संयोजित किया गया है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना 31 मार्च 2023 तक गई थी, जहां राज्य सरकार द्वारा इन कंपनियों की स्थापना के बाद से इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और परिचालन और प्रबंधन खर्चों के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन लगाया गया, दिया गया धन विनिवेश की राशि, यदि कोई हो, को कम करके किया गया है।

एसपीएसई में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन माना गया है क्योंकि एसपीएसई द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की कोई भी राशि नहीं चुकाई गई है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां एसपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को

बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, वैसे इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से हटाकर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया।

- संबंधित वित्तीय वर्ष[10] के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को पीवी पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि वे उस वर्ष में धन के निवेश के लिए सरकार द्वारा की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता हैं और इसलिए सरकार द्वारा किया गया निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 13 एसपीएसई (तीन अक्रियाशील कंपनी जैसे केईएल, पीईएल, जेसीएल के अलावा) में राज्य सरकार के निवेश की एसपीएसई-वार स्थिति के साथ राज्य सरकार के निवेश के पीवी की समेकित स्थिति और कुल आय **परिशिष्ट 5.3** में दिया गया है।

एसपीएसई में राज्य सरकार द्वारा निवेश का शेष वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में ₹ 6,114.49 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में ₹ 8,704.81 करोड़ हो गया। राज्य सरकार ने इन एसपीएसई में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹ 739.90 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि का पीवी ₹ 9,183.58 करोड़ था। 2018-19 से 2022-23 के दौरान, इन एसपीएसई में धन की लागत वसूल करने के लिए कुल आय अपेक्षित न्यूनतम रिटर्न से कम रही।

5.9 एसपीएसई जिसे घाटा हो रहा है

5.9.1 एसपीएसई जिसे घाटा हुआ

आठ[11] एसपीएसई/सरकारी कंपनी थीं जिन्हें वर्ष 2020-21 के दौरान घाटा हुआ था और तीन[12] एसपीएसई थे जिन्हें 2021-22 से 2022-23 के दौरान घाटा हुआ था, जैसा कि **तालिका 5.9** में दिया गया है।

---

[10] *सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त खातों से अपनाई गई थी, जिसमें भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की वित्तीय देनदारियों की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देनदारियां)/ 2] * 100*

[11] *जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल, जेयूयूएनएल, जेसीएल, पीईएल, केईएल, जेपीएचसीएल और जेपीपीएल।*

[12] *जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और केईएल*

तालिका 5.9: 2020-21 से 2022-23 के दौरान घाटे में रहने वाले एसपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नुकसान उठाने वाली एसपीएसई/सरकारी कंपनियों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	निवल मूल्य[13]
2020-21	8	-2,721.81	-7,185.21
2021-22	3	-2,597.72	-9,971.20
2022-23	3	-2,597.72	-9,971.20
कुल		**-7,917.25**	**-27,127.61**

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में दिखाया गया था क्योंकि 2022-23 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

2021-22 के दौरान तीन विद्युत् क्षेत्र एसपीएसई को ₹ 2,597.72 करोड़ का घाटा हुआ। **तालिका 5.10** में सूचीबद्ध दो एसपीएसई को उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार ₹ 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

तालिका 5.10: एसपीएसई जिन्हें ₹ 10 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	खाते को अंतिम रूप देने का वर्ष	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध हानि[14]
विद्युत क्षेत्र			
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	-2,088.35 (80.39%)
2	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2020-21	-506.84 (19.51%)
कुल			**-2,595.19**

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार। 2021-22 के आंकड़ों को 2022-23 के आंकड़ों के रूप में दिखाया गया था क्योंकि 2022-23 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

5.9.2 एसपीएसई की निवल संपत्ति का क्षरण

लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निवल सम्पति का कुल कीमत प्रदत्त शेयर पूँजी और लाभ, प्रतिभूतियों और लाभ और हानि खातों के डेबिट या क्रेडिट संतुलन से बनाए गए सभी भंडार का कुल मूल्य, जो संचित घाटे, स्थगित व्यय और बट्टारहित विविध व्यय के कुल मूल्य में कटौती के बाद होता जिसमे परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाया गया रिजर्व और मूल्यह्रास का बट्टे खाते में डालना शामिल नहीं होता है। विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया है।

---

13 *निवल मूल्य का अर्थ है भुगतान की गई शेयर पूँजी और मुक्त भंडार और अधिशेष को घटाकर संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। मुक्त भंडार का मतलब मुनाफे और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार हैं, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यह्रास प्रावधान को वापस लिखने से बनाए गए भंडार शामिल नहीं हैं।*

14 *राज्य सरकार द्वारा जेबीवीएनएल को ₹3,470.37 करोड़ और जेयूएसएनएल को ₹261.45 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया।*

तालिका 5.11: 31 मार्च 2023 को एसपीएसई की निवल संपत्ति का क्षरण

(₹ करोड़ में)

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते	कुल प्रदत्त पूँजी	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	संचित घाटा	निवल मूल्य	संपत्ति (डब्ल्यूडीवी)	राज्य इक्विटी 31.03.23 तक	राज्य ऋण 31.03.23 तक
जेबीवीएनएल	2021-22	3,108.93	-2,088.38	5,869.90	-11,588.19	-9,119.08	32,129.05	3,108.93	12,244.08
जेयूएसएनएल	2020-21	972.96	-506.84	229.58	-1,796.36	-823.40	8,026.00	972.96	6,566.17
जेसीएल	2021-22	1.00	0.00	0.00	-3.99	-2.99	0.98	1.00	3.92
पीईएल	2021-22	0.05	0.02	0.00	-16.42	-16.34	1.34	0.05	0.00
केईएल	2021-22	0.05	-2.50	0.00	-28.77	-28.72	23.31	0.05	43.97
झारक्राफ्ट	2021-22	10.00	0.79	3.63	-46.15	-36.15	184.27	10.00	0.00
कुल		**4,092.99**	**-2,596.91**	**6,103.11**	**-13,479.88**	**-10,026.68**	**40,364.95**	**4,092.99**	**18,858.14**

16 एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, छह एसपीएसई का संचित घाटा ₹ 13,479.88 करोड़ रुपये था, जबकि उनकी प्रदत्त पूँजी ₹ 4,092.99 करोड़ थी। इसलिए, उन एसपीएसई की निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और 31 मार्च 2023 को उनकी संचयी निवल संपत्ति (-) ₹ 10,026.68 करोड़ थी।

एसपीएसई के बकाया खातों का आयु-विश्लेषण जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है, **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.12: एसपीएसई के बकाया खातों का आयु-विश्लेषण जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है

	एसपीएसई की संख्या	एसपीएसई का नाम	कुल लेखों की संख्या
एक वर्ष (2022-23)	5	जेबीवीएनएल, जेसीएल, केइएल, पेइएल, झारक्राफ्ट	5
दो वर्ष (2021-22 और 2022-23)	1	जेयुएसएनएल	2

तालिका 5.11 में सूचीबद्ध कंपनियों में से, राज्य सरकार द्वारा 2020-21 से 2022-23 के दौरान जेबीवीएनएल (₹ 137.52 करोड़) और जेयूएसएनएल (₹ 729.96 करोड़) में इक्विटी के रूप में निवेश किया गया था। इसी अवधि के दौरान, जेबीवीएनएल को जहां ₹ 6,834.85 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया, वहीं जेयूएसएनएल को ₹ 1,983.09 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। इन वर्षों में झारक्राफ्ट को कोई सहयोग नहीं दिया गया।

घाटे में चल रही छह कंपनियों की आय और व्यय **तालिका 5.13** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.13: घाटे में चल रही कंपनियों की आय और व्यय

एसपीएसई का नाम	वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	लाभ /हानि	निवल मूल्य
जेबीवीएनएल	2021-22	6,947.56	9,035.94	-2,088.38	-9,119.00
जेयुएसएनएल	2020-21	242.37	749.20	-506.83	-823.40
झारक्राफ्ट	2021-22	26.95	26.19	0.76	-36.15
केइएल	2021-22	0.005	2.50	-2.50	-28.72
पेइएल	2021-22	0.044	0.026	0.02	-16.34
जेसीएल	2021-22	0.023	0.028	0.00	-2.99

तीन गैर-कार्यरत एसपीएसई में से पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने को उनके बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

5.10 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत एक सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा आयोजित करने और वैधानिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार उनके खातों का सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए और एक प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.11 सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

उन कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षक, जिनके खातों को 2021-22 तक अंतिम रूप दिया गया था (**परिशिष्ट 5.1** के अनुसार), सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए थे।

5.12 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा खाते प्रस्तुत करना

5.12.1 समय पर प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक आम बैठक[15] (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है। ऐसी तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके,

[15] *पहली एजीएम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर तक आयोजित की जाएगी और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर यानी 30 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।*

वार्षिक रिपोर्ट को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तारीख और अगली एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचार के लिए उक्त एजीएम में रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

5.12.2 एसपीएसई द्वारा खाते तैयार करने में समयबद्धता

पीएसयू के बकाया लेखों का आयु-विश्लेषण:

31 मार्च 2023 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में 32 एसपीएसई थे। सभी 32 एसपीएसई से वर्ष 2022-23 के खाते बकाया थे। 30 सितंबर 2023 तक, किसी भी एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने खाते सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए। 32 एसपीएसई के 107 खाते विभिन्न कारणों से बकाया थे। एसपीएसई के खातों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण **तालिका 5.14** में दिया गया है।

तालिका 5.14: लेखा प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण		एसपीएसई	खातों की संख्या
31 मार्च 2023 तक सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या		32	32
घटायें: नई कंपनियाँ जिनसे 2022-23 के लिए खाते देय नहीं थे		0	0
उन कंपनियों की संख्या जिनसे 2022-23 के लिए खाते बकाया थे		32	32
30 सितंबर 2023 तक सीएजी के लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के खाते प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या		0	0
बकाया खातों की संख्या		**32**	**107**
अन्य श्रेणी के विरुद्ध बकाया राशि का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	14	14
	दो वर्ष (2021-22 और 2022-23)	03	06
	तीन वर्ष और अधिक	15	87

स्रोत: प्राप्त वार्षिक खातों के आधार पर संकलित

5.13 सीएजी की निगरानी-खातों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन मानकों के राष्ट्रीय सलाहकार समिति जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी[16] नाम दिया गया है, के परामर्श से निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में, लेखांकन मानकों पर वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। वैधानिक निगमों को अपने खाते सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में खातों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के तहत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की आवश्यकता होती है।

5.13.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के खातों का लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा में वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक नियंत्रक की भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि वैधानिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। इस कार्य को निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग करके निष्पादित किया जाता है:

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर पूरक परीक्षा या टिप्पणी करके।

5.13.3 सरकारी कंपनियों के खातों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। वैधानिक लेखापरीक्षकों को कंपनी

[16] *01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी।*

अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित खातों के साथ-साथ वैधानिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत एजीएम में रखी जाएंगी।

5.14 सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम

5.14.1 एसपीएसई के खातों की लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-23 के लिए किसी भी एसपीएसई का कोई वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ। हालाँकि, वर्ष 2021-22 और पिछले वर्षों के लिए 19 एसपीएसई के 32 वित्तीय विवरण 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 15 एसपीएसई के 25 वित्तीय विवरण की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई और पाँच एसपीएसई के सात वित्तीय विवरणों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया।

5.14.2 वित्तीय विवरण में संशोधन

01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, एक एसपीएसई (अर्थात, राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड) ने एजीएम में रखने से पहले वर्ष 2021-22 के लिए पूरक लेखापरीक्षा के बाद अपने वित्तीय विवरण में संशोधन किया।

5.14.3 लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन का संशोधन

01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, ऐसे चार[17] मामले थे जहाँ सीएजी द्वारा आयोजित वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को संशोधित किया गया था।

5.15 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, तीन निष्क्रिय एसपीएसई सहित 32 एसपीएसई थे। 32 एसपीएसई में से किसी ने भी अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया। 32 एसपीएसई के 107 खाते बकाया थे।

2021-22 के दौरान 10 एसपीएसई (दो विद्युत् और आठ गैर-विद्युत् क्षेत्रों) द्वारा अर्जित ₹ 53.57 करोड़ के कुल लाभ में से 77.26 प्रतिशत का योगदान दो एसपीएसई (जेयूयूएनएल और जेएसबीसीसीएल) द्वारा किया गया था, जबकि 2021-22 और 2022-23 के दौरान तीन एसपीएसई द्वारा ₹ 2,597.72 करोड़ के कुल नुकसान में से एक एसपीएसई (जेबीवीएनएल) को ₹ 2,088.35 करोड़ (अर्थात, 80.39 प्रतिशत) का नुकसान हुआ।

---

17 *जेयूएसएनएल, जेपीपीएल, जिडको, जीआरडीए*

5.16 अनुशंसाएँ

(i) राज्य सरकार अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए एसपीएसई के प्रबंधन पर दबाव डाल सकती है। 32 एसपीएसई के 107 खाते बकाया थे। अंतिम खातों के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।

(ii) तीन निष्क्रिय एसपीएसई न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। तीन में से, पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड के समापन प्रक्रिया (सितंबर 2017 और फरवरी 2018 के बीच) को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकार को शेष निष्क्रिय एसपीएसई (करणपुरा एनर्जी लिमिटेड) के संबंध में भी परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।

(iii) राज्य सरकार उन एसपीएसई में घाटे के कारणों का विश्लेषण कर सकती है जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है तथा उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

राँची
दिनांक: 23 अप्रैल 2024

(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 6 मई 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक